अर्चना सक्सेना बनाम महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय और अन्य (एम.एम. पुंछी, न्यायमूर्ति.)

एमएम पुंछी और अमरजीत चौधरी न्यायमूर्ति के समक्ष

अर्चना सक्सेना,-याचिकाकर्ता।

बनाम

महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय और अन्य, -प्रतिवादी।

1988 की सिविल रिट याचिका संख्या 6663

22 अगस्त 1988.

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-रिट क्षेत्राधिकार-एम.फिल पाठ्यक्रम में प्रवेश-संस्थागत प्राथमिकता-विश्वविद्यालय आवंटित कुल अंकों पर 5 प्रतिशत वेटेज प्रदान करता है-विश्वविद्यालय के किसी अन्य पाठ्यक्रम में प्राप्त प्रतिशत पर 5 प्रतिशत का वेटेज-क्या अदालत रिट क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप कर सकती है

माना गया कि यह स्पष्ट है कि वेटेज दिए गए हैं। विश्वविद्यालय अपने छात्रों को संस्थागत प्राथमिकता देना चाहता है--एक ऐसी परिघटना जो बनी हुई है। फिर भी अतिरिक्त वेटेज निर्धारित करने में प्रतिस्पर्धा के तत्व मौजूद होने के बावजूद निष्पक्षता के सिद्धांत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दोनों विवादित सिद्धांत, जैसा कि हमें प्रतीत होता है, समान रूप से सही हैं। प्राप्त प्रतिशत पर वेटेज के पक्ष में कुछ कहना है, और समान रूप से कुल अंकों पर प्रतिशत-आयु के सिद्धांत के पक्ष में भी कुछ कहना है। यदि विश्वविद्यालय ने अपने विचार में दो ठोस सिद्धांतों में से एक (अपने तरीके से बेहतर) को विशेष रूप से चुना है, तो हमें इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कोई जगह नहीं दिखती है, खासकर भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के तहत।

(पैरा 4)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि सर्टिओरारी की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए, जिससे उपरोक्त खंड 5.1 (सी) और 3 (बी) में निहित प्रावधानों की घोषणा की जा सके, जिससे उम्मीदवारों के वार्डों को अंकों का आरक्षण/भार प्रदान किया जा सके। विश्वविद्यालय के कर्मचारी और परमादेश की प्रकृति में एक रिट, जिससे उत्तरदाताओं संख्या 1 और 2 को उनकी योग्यता के आधार पर एम.फिल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए नियुक्त किया जाता है। जो प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। मास्टर डिग्री परीक्षा में उनके द्वारा और मामले की परिस्थिति में उपयुक्त और उचित समझे जाने वाले किसी भी अन्य रिट, आदेश या निर्देश को जारी किया

जा सकता है और इस रिट याचिका की लागत भी याचिकाकर्ता को दी जा सकती है। आगे यह प्रमाणित किया जाता है कि इस रिट याचिका का अंतिम निपटान लंबित है। नौकरी से निकाले गए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 11 अगस्त1988 को आयोजित किया जाएगा। पर रोक लगाने का बहुत दयालुता से आदेश दिया जाए। फिर भी यह प्रार्थना की जाती है कि उत्तरदाताओं पर स्थगन/मोशन के नोटिस जारी किए जाएं और उनकी तामील की जाए और अनुबंध पी/1 से पी/4 के रूप में चिह्नित दस्तावेजों की मूल/प्रमाणित प्रतियां दाखिल की जाएं। बहुत दयालुतापूर्वक इसे समाप्त करने का आदेश दिया जा सकता है।

आर. पी. बाली. याचिकाकर्ता के लिए वकील।

जे. एल. गुप्ता, वरिष्ठ वकील, जसवन्त सिंह वकील। उत्तरदाताओं संख्या 1 और 2 के लिए।

निर्णय

एम. एम. पुंछी, न्यायमूर्ति. (मौखिक)

(1) याचिकाकर्ता महर्षि दयानंद का छात्र था विश्वविद्यालय,रोहतक. उन्होंने एम.फिल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन किया था शैक्षणिक वर्ष 1988-89 के लिए उक्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया। इनि-धीरे-धीरे, उसने यह दावा करते हुए प्रतिवादी नंबर 3 के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बात की उसके पास उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश का बेहतर अधिकार था। प्रतिवादी संख्या 3 ने विश्वविद्यालय कर्मचारी का वार्ड होने के आधार पर प्रवेश की मांग की थी। उस स्थिति को 5 प्रतिशत का महत्व मिलता है। उक्त विश्वविद्यालय से योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार को भी 5 प्रतिशत का वेटेज मिलता है। इन दोनों वेटेज के आधार पर प्रतिवादी संख्या 3 को याचिकाकर्ता पर तरजीह दी जा रही थी। लेकिन प्रतिवादी-विश्वविद्यालय की वापसी के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 3 को प्रवेश नहीं दिया गया है। तो, विवाद. प्रतिवादी संख्या 3 की स्वीकृति के संबंध में यह पूरी तरह से अकादमिक है और हम इसे वहीं छोड़ देते हैं।

(2) हालांकि, रिटर्न में यह कहा गया है कि एक कपूर सिंह को उसके खिलाड़ी होने के आधार पर भर्ती किया जा रहा है। खिलाड़ी होने पर भी 5 प्रतिशत का वेटेज मिलता है। इस प्रकार हमला उसी परिसर में कपूर सिंह पर स्थानांतरित कर दिया गया है और अब विवाद यह है कि प्रतिशत की गणना का सिद्धांत क्या है।

(3) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री आर. पी. बाली के अनुसार, योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों की आयु प्रतिशत पर 5 प्रतिशत वेटेज दिया जाना है। लेकिन विश्वविद्यालय-प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री जे.एल. गुप्ता के अनुसार, योग्यता परीक्षा में आवंटित कुल अंकों पर 5 प्रतिशत अंक दिए जाने हैं। श्री बाली एमडी विश्वविद्यालय से संबद्ध मेडिकल कॉलेज, रोहतक में डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम में उपलब्ध समानांतर पर अपने तर्क का समर्थन करते हैं। इसके अलावा, उनका कहना है कि कुल अंकों पर 5 प्रतिशत वेटेज देने की तुलना में प्राप्त प्रतिशत पर वेटेज देना सही था।

(4) यह स्पष्ट है कि संस्थागत प्राथमिकता को आगे बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अपने छात्रों को वेटेज दिया जाता है - एक ऐसी घटना जो कायम है। फिर भी अतिरिक्त वेटेज निर्धारित करने में प्रतिस्पर्धा के तत्व मौजूद होने के बावजूद निष्पक्षता के सिद्धांत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जैसा कि हमें प्रतीत होता है, दोनों विवादित सिद्धांत समान रूप से सही हैं। प्राप्त प्रतिशत पर वेटेज के पक्ष में कुछ कहना है और समान रूप से कुल अंकों पर प्रतिशत के सिद्धांत के पक्ष में भी कुछ कहना है। यदि विश्वविद्यालय ने अपने विचार में दो ठोस सिद्धांतों में से एक (अपने तरीके से मजबूत) को विशेष रूप से चुना है, तो हमें इस मामले में हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश नहीं दिखती है, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत तो और भी अधिक। ट्यूशन अनिवार्य रूप से, हमें याचिकाकर्ता के तर्क को खारिज करना होगा एक में दूसरे सिद्धांत का पालन करने का जो उदाहरण दिया गया है उसके बावजूद विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय।

(5) अंत में, श्री बाली द्वारा यह तर्क दिया गया कि हरियाणा में विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों के शिक्षकों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण गलत है। हमें उस प्रश्न को अकादमिक रूप से निर्धारित करने के लिए तथ्यों के वर्तमान सेट पर नहीं बुलाया जाता है।

(6) उपरोक्त कारणों से, यह याचिका विफल हो जाती है और इसे खारिज कर दिया जाता है। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

तुषार शर्मा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी , कैथल, हरियाणा